Business Standard
4 भोपाल
2 अगस्त 2013, शुक्रवार

जहरीले कचरे का जोखिम अब भी

शशिकांत त्रिवेदी
भोपाल, 1 अगस्त

नई दिल्ली स्थित संगठन सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की बंद पड़ी फैक्टरी के आस-पास भूमि और जल प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर आगाह किया है। सीएसई ने चेताया कि पूरा ध्यान 350 टन रासायनिक कचरे पर है लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भूमिगत जल प्रदूषित हो गए हैं।

सीएसई ने मिट्टी एवं भूमिगत जल, रासायनिक कचरे के निपटान के लिए दिल्ली में 25-26 अप्रैल को संबंधित पक्षों का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है।

सीएसई के उप महानिदेशक चंद्र भूषण की बात से तो कम से कम यही लगता है। उनका कहना है, 'राज्य के अधिकारियों के अलावा सम्मेलन में बाकी सभी पक्ष शामिल हुए थे।' उन्होंने कहा कि रासायनिक कचरे से फैले

सीएसई ने मिट्टी एवं भूमिगत जल, रासायनिक कचरे के निपटान के लिए दिल्ली में 25-26 अप्रैल को संबंधित पक्षों का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है।

प्रदूषण से आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

भूषण ने कहा कि विशेषज्ञ समूह के अनुसार यूनियन कार्बाइड के परिसर में जमा 350 टन रासायनिक कचरा एक छोटा हिस्सा है, क्योंकि विभिन्न स्थलों और एसईपी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कचरा जमा हैं। उन्होंने कहा, 'मिट्टी और भूमिगत जल को प्रदूषण मुक्त करने में कम से कम 5 साल का समय लग जाएगा।'

हालांकि इस कार्य के लिए रकम की दरकार होगी और लोगों की उम्मीदें सरकार पर ही टिकीं हैं।

रासायनिक कचरे से निजात दिलाने के लिए भूषण ने एक कार्य योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, '2009-2013 के बीच अध्ययन हुए हैं, उनसे यही निष्कर्ष निकला है कि प्रदूषण बड़े स्तर पर है और सरकार अगर आक्रामक तरीके से काम करती है तो चीजें ठीक करने में लगभग 5 साल लग जाएंगे।'

कार्य योजना

विशेषज्ञ समूह ने रोक-थाम और हानिकारक रासायनिक कचरे के निपटाने के लिए मध्यम से लंबी अवधि के उपाय सुझाएं हैं। समूह ने जो उपाय सुझाएं हैं उनमें कचरा स्थल और एसईपी क्षेत्र में लोगों के जाने पर रोक, एसईपी क्षेत्र में निर्माण रोक और मॉनसून के समय इस स्थल से जलों के बहाव को रोकना आदि शामिल हैं।

कार्य योजना में स्थल की खुदाई और सभी कचरों को हटाने के भी सुझाव दिए हैं।

भूषण ने कहा, 'विशेषज्ञ समूह में बनी आम राय के आधार पर ये कार्य योजना तैयार हुई है। सभी इस बात पर एकमत थे कि संस्थागत बाधाओं को दूर करना अति आवश्यक हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार को इस दिशा में तेजी से काम करना चाहिए।'